

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 167 / 2020

बउनवान

नवलकिशोर पुत्र देवलाल धाकड़ निवासी ग्राम बावड़ीखेड़ा तहसील छबड़ा जिला बारों (राज.)
(अपीलांत)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, छबड़ा जिला बारों

(रेस्पोंडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1-श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर अभिभाषक (अपीलांत)

2- पेरोकार सरकार

(रेस्पोंडेन्ट)

निर्णय दिनांक 20.07.2020

अपीलांत ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा के प्रकरण संख्या 1004/2020 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 02.03.2020 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांत को वाके ग्राम बमोरा की सरकारी भूमि किस्म सिवायचक सम्वत् 2076 में खसरा नम्बर 10/1 की रकबा 10 बिस्वा भूमि पर फसल गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 25/- रुपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट सरिस्ता देखी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया।

इस पर अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया और अपीलांत के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण में अपीलांत के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की उभयपक्ष बहस सुनी गई।

अपीलांत के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत के विरुद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलांत को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया और न ही अपीलांत को कभी बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में अपीलांत को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये जाने पर, अधी. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाने पर दिनांक 16.7.2020 को अपीलांत को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया है तब से अपीलांत न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की झूठी व मनगढन्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांत को सजायाब किया जाकर उक्त निर्णय पारित किये जाने में भारी भूल की है। अधी. न्यायालय ने अपीलांत की अनुपस्थिति में निर्णय दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधी. न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 2.3.2020 की सर्वप्रथम जानकारी पुलिस द्वारा अपीलांत को गिरफ्तार करने पर दि. 16.7.2020 को ही हुयी, जिसके बाद नकल हेतु आवेदन करने पर 16.7.2020 को ही नकल प्राप्त करने पर अपील अंदर मियाद पेश है।

अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.3.2020 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांत को दोषमुक्त करने की कृपा कर जेल से मुक्त करवाने की कृपा करें।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांत द्वारा सरकारी भूमि किस्म सिवायचक पर फसल गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांत द्वारा गतवर्ष में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तावान दण्डित किया जाकर मौके पर भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांत द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा कम है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांत की सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपीलांत वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा में अनुपस्थित रहा है। अपीलांत द्वारा ग्राम बमोरा की सिवायचक भूमि खसरा नं० 10/1 की रकबा 10 बिस्वा भूमि पर फसल गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण किया गया है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा कम है और अपीलांत दिनांक 16.7.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 1004/2020 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत पारित आदेश दिनांक 2.3.2020 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांत को उक्त आदेश से दी गई (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा में से अब तक अपीलांत द्वारा भुगती गई सजा को छोड़कर शेष सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार छबडा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की 2 बार जाँच करावे, यदि अपीलांत का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम बमोरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 10/1 की रकबा 10 बिस्वा भूमि किस्म सिवायचक पर फसल गेहूँ की बोई जाकर किया गया अतिक्रमण नहीं पाया जावे, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 1004/2020 में पारित आदेश दिनांक 2.3.2020 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.3.2020 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति० जिला कलक्टर, बारों